



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190]  
No. 190]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 1980/आश्विन 9, 1902  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 1980/ASVINA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## बाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 37 आई टी सी (पी एन)/80

नई दिल्ली 1 अक्टूबर, 1980

विषय—विदेशी आर्थिक सहायता निधि (आई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए 2.7 बिलियन येन ऋण के अधीन माल व आयातों और सेवाओं व संपत्ति में लाइसेंस शर्तें।

विदेशी आर्थिक सहायता निधि (आई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए 2.7 बिलियन येन ऋण के अधीन टेनिकम्युनिकेशन परियोजना, (2) के लिए माल के आयातों और सेवाओं के संबंध में आयात लाइसेंसों के नियंत्रण को नियंत्रित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना में दी गई हैं जानकारी व निम्न अधिसूचित की जाती हैं।

[मिनिम सं० आई टी सी 23/4/80 में जारी]

मणि नारायण स्वामी मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

बाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या 37 आई टी सी (पी एन)/80, दिनांक 1-10-80 का परिशिष्ट।

विदेशी आर्थिक सहायता निधि (आई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए 2.7 बिलियन येन ऋण के अधीन टेनिकम्युनिकेशन परियोजना (II) के लिए माल व आयातों और सेवाओं के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

खण्ड-1-सामान्य शर्तें

1 (1) महानिदेशक डाक्टर की दूर संचार परियोजना की आयात आवश्यकताओं व वित्तदान के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सह-

योग निधि (आई सी एफ) द्वारा प्रदान किया गया 2.7 बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खुला है। तबनुसार इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र माने जायेंगे।

1 (2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किये जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय तकनीकी विकास/पूँजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निष्पादी कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सी) का मूल्य 3,000 मिलियन (लागत बीमाभाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा-शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनियम दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि का प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78-आई टी सी (पी एन) 74 दिनांक 6 जून 1974 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतिक दर पर निर्धारित किया जाएगा। जिसमें यह भी उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारों और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सी) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य का नाम डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक 'जापानी येन ऋण संख्या आई टी सी-5 होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में 'एस/जे एन' काड होगा। महानिदेशक डाक्टर को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा। जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1 (3) जापान-बीमा भाड़ा के आधार पर केवल महानिदेशक डाक्टर का नाम में ही लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) महानिदेशक डाक तार की सुविधा पर निर्भर करने हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किये जा सकते हैं। लेकिन कुल मूल्य 3,000 मिलियन (लागत बीमा भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि महानिदेशक डाक तार द्वारा आवेदन करने पर 31-12-84 तक दी जा सकती है। हमसे आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस से संलग्न माल और सेवाओं की सूची जोकि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् स्थापित हो, तक प्रतिबंधित है।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात-लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होने और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपये में भारत में किया जाएगा। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस-धारी द्वारा दिए गए उन त्रय आदेशों से है जो या तो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक या विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित त्रय संविदा हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकर्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं हैं।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर बैंकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि लेख के पूर्ण वस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि में चार, महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई-1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आवेदन क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को मम्बई लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आवेदन देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पावता के आधार पर विचार किया जाएगा वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पावता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को परेषित करेंगे।

लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों के संबन्ध में बैंक गारंटी साक्ष्यपत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकारपत्र तुल्य रूपया जमा कराने की स्वीकृति आवेद की सुविधाओं की अनुमति देगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देवे चाहिए। माल के पोत लदान पर अन्ध-धलंग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकब आधार

पर अर्थात् पोतलदान वस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक का किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए।

"साख पत्र की प्राप्ति के बाद ..... महीने परन्तु अधिक से अधिक ..... के अन्त तक पूर्ण किया जाता है।"

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-84 के बाद की न हो।

**खण्ड-2-संभरण ठेके का समन्वित करने समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें**

2(1)(क) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अधिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपय में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपय या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। त्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) प्रो०ई०सी०एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश अनुबंध-2 में दिए गए हैं। लेकिन साधारणतया, माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :—

(क) बोली लगाने के लिए नियंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचित होने वाली कम से कम एक प्रखण्ड में विज्ञापित करने पड़ेगे।

(ख) बोली के बाण्ड या बोली लगाने की गारंटी सामान्य आवश्यकता है परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले, हतोत्साहित हो जाएं।

(ग) बोली खुल जाने के बाद असफल बोलीकारों को यथा शीघ्र बोली बाण्ड या गारंटियां रिहा कर देनी चाहिए।

2(3) जिन मामलों में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा उचित न हो वहां निधि निम्नलिखित बैंकस्थित क्रियाविधि अपनाएंगी :—

(क) जहां आयातक के पाम विश्वसनीय कारण हों या अपने उपकरण का उचित मानकीकरण रखता हो।

(ख) जहां पर पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो।

(ग) जहां अधिप्राप्ति में शामिल धनराशि इतनी कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से विलचरपी न ले या यह कि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के फायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्वपूर्ण हों।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त जहां निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया को अनुपयुक्त समझे उदाहरणार्थ आपान अधिप्राप्ति के मामले में।

ऊपर संकेतित मामलों में निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इस ढंग से अपनाई जाए जिससे कि जहां तक उचित हो पूर्ण संभाव्य सीमा तक औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके :—

(1) औपचारिक निविदा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना

(2) अनौपचारिक अन्तर्जातीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति ।

(3) एक संभरक से सीधा क्रय ।

महानिदेशक डाक तार को विशेष कारण/प्रोत्थित्य बताने वाली बोलियों के मूल्यांकन और तुलना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जिस पर न्यूनतम भूतत्वांकित बोली आधारित हो और इसकी तीन प्रतियों के साथ बोली विभेदण विवरणी शीट, दस्तावेजी साक्ष्य सहित यदि कोई हो तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए जो विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आईसीएफ) से उसका आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्रय संविदा, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) (जापान अनुभाग) द्वारा श्री०ई०सी०एफ० का केवल तभी अधिसूचित किया जाएगा जबकि रिपोर्ट आदि का आई०सी०एफ० से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

2(4) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक टोकियो द्वारा 1979-80 के लिए आईसीएफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आईसीपी-5 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसका प्रयोग नीचे खण्ड 6 में दिया गया है।

2(5) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(6) संभरक की प्राप्तता

संभरक पात्र स्रोत देशों का नागरिक या पात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा यथार्थरूप से शासित वैध व्यक्ति होगा। उसे निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी पड़ेंगी :—

(क) मात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा अधिकतर अभिदस्त शीयर रखे जाएंगे।

(ख) अधिकतर पूर्ण कालिक निवेशक पात्र स्रोत देशों के नागरिक होंगे।

(ग) ऐसे वैध व्यक्ति पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत होंगे

2(7) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा प्राप्तता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

“मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि संभावित किया जाने वाला माल ..... में (पात्र स्रोत देश) उत्पादित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30% से कम है :—

आयातित लागत बीमा-भाड़ा मूल्य आयातित शुल्क  $\times 100$ ”

संभरक का जहाज पर निशुल्क मूल्य

और

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि—  
(पात्र स्रोत देश का नाम) में— (कम्पनी का नाम)  
समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा नियंत्रित है।

2(8) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिस वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तदान किया जा सकता है, बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मदवार आधार पर आयातित भाग 30% से कम हो :—

आयातित लागत बीमा-भाड़ा आयात शुल्क

भाड़ा मूल्य

$\times 100$ ”

संभरक का जहाज पर निशुल्क मूल्य

खण्ड-3—संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आईसीएफ) के बीच दूर संचार परियोजना (2) के लिए येन क्रेडिट आईसीपी-5 (परियोजना सहायता) से सम्बन्धित 8 मई, 1980 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आईसीएफ) के बीच येन क्रेडिट सं० आईसीपी-5 से सम्बन्धित 8 मई, 1980 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी और आईसीएफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में)

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के सम्बन्ध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और उन उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल माल की संपूर्णता के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोतलदान से कम से कम 4 सप्ताह पूर्व दूतावास को सूचना देना जिसे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की ह्रास अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक स्पॉरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड-4—विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (आईसीएफ) द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर महानिदेशक डाक एवं तार और विदेशी सम्भरकों दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरक द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां, संगत वैध आयात लाइसेंस की 2 फोटो प्रतियां सहित, जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय-वस्तु के लिए अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, तार संचार परियोजना (2) के लिए येन क्रेडिट सं० आईसीपी-5 (परियोजना

सहायता) के अन्तर्गत विस्तार करने के लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (आई सी एफ) की संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

#### खण्ड-5—विदेशी संभरकों को भुगतान-साख-पत्र क्रियाविधि

5(1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (आई सी एफ) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग द्वारा महानिदेशक, डाक एवं तार और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद महानिदेशक, डाक एवं तार विभाग की सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सीएएफ कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूसीओ बैंक विल्डिंग, संभव मार्ग नई दिल्ली को अनुबंध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सीएएफ खण्ड ए अनुबंध-4 के रूप में संलग्न प्रपत्र में एक प्राधिकार पत्र भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिए) या अनुबंध-6 (सेवाओं के लिए) के रूप में संलग्न प्रपत्र में सम्बन्धित विदेशी संभरक के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए जारी करेगा। प्राधिकार पत्र की प्रतियाँ (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि) (आईसीएफ), भारतीय दूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी।

5(2) प्राधिकार-पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक टोकियो अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार सम्बन्धित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (आईसीएफ) भारतीय दूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, को भी भेजेगा।

सी ए ए ए से प्राधिकार-पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे ही सभी प्राधिकार पत्र/साख-पत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होंगी।

5(3) माल का पोत लदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साखपत्र खोलने, रख-रखाव और उसके प्रचालन के सारे खर्चे विदेशी संभरकों के लेखों से लिए जाएंगे। इसलिए, भारतीय बैंक, टोकियो विदेशी बैंक से इन सभी खर्चों की वसूली करेगा, सौदे से सम्बन्धित दस्तावेजों को भेजने की व्यवस्था करने के लिए खर्च और अन्य प्रासंगिक खर्च भी संभरक द्वारा उठाए जाएंगे।

भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा संभरक को माल के अज्ञान पर निःशुल्क मूल्य के भुगतान की तारीख और आईसीएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख के बीच अन्तराल के लिए भारतीय बैंक 25-3-1980 को भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ उनके द्वारा किए गए समझौते के नियम एवं शर्तों के अनुसार ब्याज की वसूली करेगा और भारतीय दूतावास टोकियो से उसकी प्रतिपूर्ति करवा लेगा। जापान में भारतीय दूतावास द्वारा इस ब्याज के भुगतान से हुए खर्च [खण्ड 6 (4) के अनुसार] डाक एवं तार विभाग से वसूल किए जाएंगे।

#### खण्ड-6—सहायता निक्षेप करण के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक टोकियो संगत प्राधिकारपत्र के परिशिष्ट में संकलित अनुसार महानिदेशक, डाक एवं तार के प्राधिकृत बैंकर की अप्रत्यक्ष कार्य जहाजरानी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि महानिदेशक, डाक एवं तार ने जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, लॉस एंजेलिस, विल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया है। विदेशी संभरक को दिए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपया मार्चजनिक सूचना सं०-74 आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-1974 में निर्धारित तरीके से भारत सरकार के लेखों में जमा किया जाएगा। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाले विनियम की दर भुगतान की तारीख को लागू विनियम की वह मिश्रित दर होगी जो मार्चजनिक सूचना सं०-109-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8 आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-1976 में निर्धारित तरीके के अनुसार निर्दिष्ट की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की मार्चजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांस-843 सिविल डिपॉजिट्स-डिपोजिटिंग फार परचेजिंग एट्टा एण्ड, परचेजिंग अण्डर क्रेडिट्स। लोन एग्जिस्टिंग लोन फ्रॉम वि गवर्नमेंट ऑफ जापान 27 बिलियन येन क्रेडिट सं० आईटीसी-5 फार टेलिकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट (2)" होना चाहिए। किन्तु 31-5-1974 की उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित ब्याज खर्च और निक्षेप की गणना से सम्बन्धित व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी क्योंकि केंद्रीय सरकार के विभागों द्वारा किए गए आयातों के सम्बन्ध में कोई भी ब्याज खर्चा वसूल नहीं किया जाता है।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लॉस एंजेलिस, विल्ली में सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना संख्या-184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-1968, सं० 233 आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-1968 सं० 132 आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं०-74 आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 में यथानिर्धारित तरीके में जमा होनी चाहिए।

6(3) भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अनिवार्य धनराशि सेवा खर्चों को निम्न भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। जापान के विभिन्न कालों में भरने समय आयातकों/उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चन कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जानी वाली सार्वजनिक सूचना संख्या-132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना संख्या-74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना जापान के कालम "धन परपण और प्राधिकार (यदि कोई हो) के पूर्ण वीर" में निरापवाद रूप से निदिष्ट किए गए हैं। अज्ञानता जापान में निम्नलिखित भीरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :-

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक;

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं;

(ग) विदेशी संभरक का भुगतान करने की तिथि।

उनके पश्चात् सी ए ए ए द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संबंधित वेतें हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए

खजाना चालान रूपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा  
ई. ए. ए. को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी - भारत में आयातक के बैंक का यह सुनिश्चित करता चाहिए  
कि स्थायी या निक्षेप भारतीय बैंक, टाकिया से अदायगी की  
सूचना और अपरिवर्तनीय पत्र लदान दस्तावेजों की प्राप्ति  
के 10 दिनों के भीतर निगमवाद रूप में किया जाना चाहिए  
और यह कि इसके तत्काल बाद सी. ए. ए., विल मन्त्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली का संचित कर दिया  
जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक का लाइसेंस की मुद्राविनियम  
नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए  
और अपरिवर्तनीय 'एस' प्रपत्र भारत में रिजर्व बैंक आफ इंडिया का भेजना  
चाहिए।

भारतीय दूतावास टाकिया द्वारा भारतीय बैंक, टाकिया का किए गए  
व्याज आदि के आधार पर देन भुगतान के समतुल्य रूप की गणना भी  
उपरोक्त खण्ड-6 की कंडिका 6(1) में उल्लिखित तरीके से की जाएगी  
और उसे मध्य एशिया अधिकांश विदेश मन्त्रालय के नाम में जमा किया  
जाएगा। जिसके प्रयाजनाथ सी. ए. ए. ए. उचित बीजक जारी करेगा।

#### खण्ड 8-विविध व्यवस्थाएं

##### 8(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पत्र लदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष  
धनराशि व बार में साख्तपत्र आयात के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता  
लेखा ए. ए. ए. पर शा. निर्यात आर्थिक कार्य विभाग, विल मन्त्रालय यू. सी. ओ. बैंक  
बिल्डिंग सदन मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

##### 8(2) सम्बरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में किए गए किसी उन विशेष  
उपबंधों से सभरक ना अवगत करा देना चाहिए जो मान के लाने से जाने  
में सभरक पर प्रभाव डालनी हो।

##### 8(3) विवाद

अतः समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और सभरकों के बीच कोई विवाद  
उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी।  
भारतीय बैंक टाकिया द्वारा किए गए भुगतान में पहले सभरक द्वारा  
पूरी की जाने वाली शर्त अनुबन्ध 3 में "भुगतान की शर्त" के अंतर्गत  
अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद  
के निपटान में सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल हानी चाहिए।

##### 8(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठे खड़े होने वाले किसी मामले  
या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ देन अडिक्ट  
समझौते (पण्यवस्तु सहायता) के अधीन सभी आधारा को पूर्ण करने के लिए  
आत राखरक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों अनुदेशों या  
आदेशों का लाइसेंसधारियों को तुरन्त पालन करना होगा।

##### 8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपयुक्त खण्डों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने  
पर आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की  
जाएगी।

##### 8(6) अनुबन्धों की सूची

1 अनुबन्ध 1 पात्र छोट देशों की सूची

2 अनुबन्ध 2	अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्गदर्शक
3 अनुबन्ध 3	प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4 अनुबन्ध 4	प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र
5 अनुबन्ध 5	साख्तपत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयात के लिए लागू)
6 अनुबन्ध 6	साख्तपत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

#### अनुबन्ध 1

##### पात्र छोट देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) ओ पी ई सी से मिल विकासशील देश

(ख) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ख-1) मान-ओपी. ओ. सी. विकासशील देश

1 अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिस्र

मोरोको

तुनीशिया

2 अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला

बोत्सवाना

बुरुंडी

कैमरून

केप बर्डी द्वीपसमूह

कन्द्रीय अफ्रीका गणतन्त्र

चाड

कमरो द्वीपसमूह

इथियोपिया

जाम्बिया

घाना

गिनी

ग्राइबरी वास्ट

कीनिया

लेसोथो

साइरिया

मालागासी गणतन्त्र

मलावी

माली

मॉरिटानिया मॉरिशस

मोजम्बीक

नाइगर

पुर्तगाली गिना

रियूनियन

रोडेशिया

खान्दा

मेट हेमिना और डेप (2)

साओटोम और प्रिन्साइड

सेनेगल

सेजिमिन

सियरा लियोन

सोमालिया  
सूडान  
स्वाजीलैंड  
टेंरी प्रायद्वीप और इस्तास  
टोगो  
युगान्डा  
तंजानिया गणतंत्र संघ  
अपर बोल्टा  
आइरे गणतंत्र  
जाम्बिया

### 3. अफ्रीका उत्तरी और केन्द्रीय

बेहमस  
बारबोडोज  
बेसाइज  
बरमुडा  
कोस्टारिका  
क्यूबा  
डोमिनिकन गणतंत्र  
एल साल्वेडोर  
गुवातेमाल  
ग्वाटेमाला  
हैती  
होण्डुरस  
जमैका  
मार्टिनिक  
मेक्सिको  
नीदरलैंड्स एन्टिलीज  
निकारागुवा  
पनामा  
सेन्ट पियरों और मिकेलोन  
ट्रिनिडाड और टोबैगो  
वेस्ट इण्डीज (शाखा) एन०आर०ई०  
(क) सम्मिलित राज्य (1)  
(ख) भाषित (2)

- (1) पहले स्पेनी गिनी क प्रदेश, फरनेन्डो पो द्वीप समूहित
- (2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—  
असेन्शन, ट्रिस्टन डा इन एक्सोसिटिस, नाइटिंगेल गण।
- (3) मुख्य द्वीप समूह, भरबी, बोनाहरे, क्युराकाओ साहा, सेन्ट मार्टिन (वर्षण भाग)

### 4. दक्षिणी अमेरिका

अर्जेन्टीना  
बोलिविया  
ब्राजील  
चिली  
कोलम्बिया  
फाल्कलैंड द्वीप समूह  
फ्रांसिसी गिनी  
गुयाना  
पाराग्वे  
पीरू  
सुरिनाम  
उरुग्वे

### 5. मध्य पूर्वी एशिया

बेहरीन

इजराइल  
जोर्डन  
लेबनान  
ओमन  
सिरिआई अरब गणतंत्र  
यूनाइटेड अरब एमिरात  
यमन अरब गणतंत्र (3)  
यमन जनवादी डी०आर० (4)

### 6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान  
बांगला देश  
भूटान  
बर्मा |  
भारत  
मालदीव  
नेपाल  
पाकिस्तान  
श्रीलंका

### 7. सबूर पूर्वी एशिया

बर्मा  
हांगकांग  
खमेर गणतंत्र  
कोरिया गणतंत्र  
लाओस  
मकाओ  
मलेशिया  
फिलिपाइन  
सिंगापुर  
ताइवान  
थाईलैंड  
तिमोर  
वियतनाम गणतंत्र  
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

### 8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह  
फिजी  
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप  
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)  
नौर  
न्यू कालेडोनिया  
न्यू हेब्रिड्स (त्रि और फ्रे)  
हिडू  
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त  
राज्य (6)  
पापुआ न्यू गिनी  
शोलामन द्वीप समूह (त्रि)  
टोंगा  
वालिस और फुतुना  
पश्चिमी सामोवा

### 9. यूरोप

साइप्रस  
जिब्राल्टर

शोक	खण्ड 3.01	विशिष्टीकरणों का स्पष्टीकरण
मास्टा	खण्ड 3.05	मापदण्ड
लैम	खण्ड 3.06	ब्राण्ड नामों का उपयोग
पुकी	खण्ड 3.07	संविदाओं के अन्तर्गत व्यय
यूरोस्लाविया	खण्ड 3.08	बोलियों का मूल्य
(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, बोनिमिका, वेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफी) मेबिल भगुइला, सेन्टमुसिया और सेन्ट क्रिस्टेन्ट	खण्ड 3.09	संविदा मूल्य
(2) मुख्य द्वीप : मोल्सेरल, मेमान, तर्क और काइकोस और ब्रिटिश बरजिन द्वीप समूह	खण्ड 3.10	मूल्य संयोजन धाराएं
(3) अजमान, बबल, कुजाहरह, राम अम सेमाह शरजाह और उम अम कबैनेन	खण्ड 3.11	प्रतिम भुगतान
(4) अरब और विभिन्न सुल्तान और अमीरन सहित ।	खण्ड 3.12	गारंटियां मिश्रित बांड और रोक रखा गया धन
(5) सोसायटी द्वीप समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए, आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोट, जाम्बियर पुप और मालेसम द्वीप समूह ।	खण्ड 3.13	बीमा
(6) वैसिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रवेश : कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)	खण्ड 3.14	चुकाई गई क्षति और बोमस धाराएं
(क2) ओ० पी० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश	खण्ड 3.15	बाध्यकर स्थितियां (कोर्ने मेज्जूर)
अल्जीरिया	खण्ड 3.16	भाषा की व्याख्या
बोनिफिया	खण्ड 3.17	विवादों का निपटारा
नीथिमाई अरब गणतंत्र	अनुच्छेद 4	बोली खोलना, मूल्यांकन और संविदा प्रदान करना
रोमान	खण्ड 4.01	बोली प्रामाणिक करने और बोली लगाने के बीच का समय
नाइजीरिया	खण्ड 4.02	बोली खोलने की क्रियाविधि
इक्वेडोर	खण्ड 4.03	बोलियों का स्पष्टीकरण या परिवर्तन
बेन्गुएला	खण्ड 4.04	क्रियाविधि गोपनीय रखना
ईरान	खण्ड 4.05	बोलियों का परीक्षण
ईराक	खण्ड 4.06	बोलियों के पूर्ण की शर्तें
कुवैत	खण्ड 4.07	बोलियों का मूल्यांकन तथा तुलना
कातार	खण्ड 4.08	बोलियों को रद्द करना
सउदी अरब	खण्ड 4.09	संविदा प्रदान करना
अबुधाबी	अनुच्छेद 5	सलाहकारों के उपयोग के लिए मार्ग दर्शन
इन्डोनेशिया	खण्ड 5.01	सलाहकारों की स्वतन्त्रता
	खण्ड 5.02	सलाहकारों का व्यय

संलग्न वस्तु :—पात्र खोत देश

ऋण के अन्तर्गत माल प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन

## अनुच्छेद-2

ऋण के अग्रणी अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन  
विषय सूची की तालिका

अनुच्छेद संख्या	शीर्षक
अनुच्छेद 1	सामान्य
खण्ड 1.01	प्रस्तावना
खण्ड 1.02	औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने से भिन्न क्रियाविधि
खण्ड 1.03	संविदाओं की किस्म और आकार
अनुच्छेद 2	विकास और इससे पूर्व की शर्तें
खण्ड 2.01	विकास
खण्ड 2.02	बोली लगने से पूर्व की शर्तें
अनुच्छेद 3	बोली लगाने वाले वस्तुनिष्ठ
खण्ड 3.01	निधि के लिए मन्दर्भ
खण्ड 3.02	बोली बाण्ड अथवा गारंटियां
खण्ड 3.03	संविदा की शर्तें

## अनुच्छेद-2

सामान्य

## खण्ड 1.01 प्रस्तावना

(क) ये निर्देशन बिन्दु उन नियमों को बताते हैं जो कि विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (इसके बाव "निधि" कहलाए) उस परियोजना के विकास के लिए माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए सामान्यतः लागू करती है जिसके लिए निधि अपने ऋण द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त प्रदान करती है ।

(ख) निधि के ऋण की रकम की मितव्ययता, दक्षता और उन देशों के बीच बिना भेदभाव की भावना को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उपयोग करना होगा जो कि उपर्युक्त माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए पात्र है (ऐसे देश इसके पश्चात् "पात्र खोत देशों" के नाम से पुकारे गए हैं) । निधि यह विचार रखती है कि बहुत से मामलों में औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा, परियोजना विकास के लिए माल और सेवाओं का आर्थिक और दक्षतापूर्ण अधिप्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है । अतः निधि अपने ऋणी से साधारणतः अपेक्षा करता है कि वह औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से माल तथा सेवाओं को प्राप्त करे ।

(ग) निधि द्वारा वित्त दान की गई किसी विशेष परियोजना लिए इन निर्देशन बिन्दुओं का लागू होना, बोली लगाने के दस्तावेज और अधिप्राप्ति की क्रियाविधियाँ जिस सीमा तक निधि द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षा के अधीन हैं कि वे इन निर्देशन बिन्दुओं के अनुरूप हैं पात्र होत देश और अपात्र अंतर्देशों में अनुमति प्राप्तियों के लिए प्राथमिकता उस परियोजना के लिए निधि द्वारा प्रदान किए गए ऋण के सविदा सम्बंधी दस्तावेजों में निर्धारित किए जाएंगे।

(घ) किसी भी परियोजना पर माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए अन्तिम उत्तरदायित्व परियोजना के स्वामी पर होता है। चूंकि स्वामी प्रायः ऋणी भी होता है इसलिए इन मार्ग निर्देशन बिन्दुओं में ऋणी शब्द का प्रयोग मालिक के लिए भी किया गया है। परियोजना के लिए प्रदान किए जाने वाले माल और सेवाओं के लिए बोली लगाने वालों के विषय में ऋणी के अधिपक्ष और दायित्व ऋणी द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों द्वारा गारंटी किए जाते हैं इन मार्ग निर्देशन बिन्दुओं द्वारा नहीं, ये निर्देशन बिन्दु केवल ऋणी और निधि के बीच क्या सम्बन्ध हैं इससे सम्बन्धित हैं।

#### खण्ड 1.02 औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से निम्न क्रियाविधियाँ

कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा उचित न ठहरे और निम्नलिखित मामलों में निधि अन्य दूसरे तरीके अपनाएँ ---

- (क) जिन मामलों में ऋणी के पास अपने उपस्कर का एक उचित सान्कीकरण कायम रखने के लिए विश्वसनीय कारण हो,
- (ख) जिस मामले में पात्र सम्भरणों की संख्या सीमित हो जैसे विद्यमान उपस्कर के लिए फालतू पुर्जों की संख्या,
- (ग) जिस मामले में अधिप्राप्ति के लिए लगी हुई धनराशि इतनी कम है कि विदेशी पाटियों स्पष्ट रूप से इच्छुक न हो या यह कि अन्तर्देशीय भार प्रशासकीय भार औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के लाभ से महत्वपूर्ण हो।
- (घ) जिस मामले में उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की क्रियाविधियों का लागू करना अनुचित समझता है या निधि ऐसी क्रियाविधि की अनुपयुक्त समझता है उदाहरणार्थ आपातकालीन अधिप्राप्ति के मामले में। ऊपर उल्लिखित मामलों में निम्नलिखित मार्ग प्राप्ति का कामूना इस प्रकार लागू किया जाए कि वह औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा क्रियाविधि का पूर्ण सम्भव सीमा तक यथा उपयुक्त पालन करे।

- (1) औपचारिक भुविदा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा
- (2) अन्तीपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय पतियोगात्मक अधिप्राप्ति
- (3) एक ही सम्भरण में सीधे ही खरीद।

#### खण्ड 1.03 सविदाओं की किस्म और प्रकार

संविदाएँ निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मदी के या एकमुष्ट कीमतों के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के सम्बन्ध के आधार पर, प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती हैं और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में भुनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाएँ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं हैं।

विस्तृत प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए, अलग अलग सविदायेँ जिनके लिए बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं, जब भी सूविधाजनक हो इतने बड़े आकार को होनी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर बोलियाँ आकर्षित कर सकें। दूसरी ओर, यदि तकनीकी और प्रशासकीय रूप में

किसी परियोजना को विशिष्ट प्रकार की संविदाओं में विभक्त करना सम्भव है और इस प्रकार किया हुआ विभाजन लाभकारी होने की सम्भावना है तो विस्तृत रूप से औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा को अनुमति प्रदान करने के लिए परियोजना इस प्रकार विभाजित की जाएगी। इजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए इसी मार्ग द्वारा प्रदान की जाने वाली संविदाएँ (उनकी संविदाएँ) यदि देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभप्रद प्रमाण करे तो वे स्वीकार्य हैं।

#### अनुच्छेद-2

##### विज्ञापन और पूर्व अर्हताएँ

#### खण्ड 2.01 विज्ञापन

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएँ बोली आमंत्रित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित होनी चाहिए। विज्ञापन के बोली आमंत्रित करने की प्रतियाँ पात्र स्वीकृत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए।

#### खण्ड 2.02 बोली लगाने वालों की पूर्व अर्हताएँ

जिस मामले में निधि बोली लगाने वालों की पूर्व अर्हताओं की आवश्यक समझती है, उसमें निधि बोली लगाने से पूर्व की शर्तों को मान्यता प्रदान कर सकता है। यह निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

- (1) प्रत्येक पार्टी का समान कार्य में अनुभव और भूतकालीन निष्पादन,
- (2) कर्मचारीगण, उपस्कर और संयंत्र के सम्बन्ध में उसकी सामर्थ्य और
- (3) उसकी आर्थिक स्थिति।

पात्र समझे जाने के लिए इच्छा रखने वाले संविदाकारों की संक्षिप्त विशिष्टीकरण उपलब्ध कराएँ जाएँगे। यदि पूर्व अर्हताएँ प्रयोग की गई हों तो उन सभी पाटियों की बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी जो पात्र पाई गई हैं।

#### अनुच्छेद-3

##### बोलियों के दस्तावेज

#### खण्ड 3.01 निधि का सम्बन्ध

बोली लगाने वाले दस्तावेज निम्नलिखित भाषा में होने चाहिए ---

“... (ऋणी का नाम)

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि में एक ऋण ... (ऋण के नाम) से ... (परियोजना का नाम) की कीमत के मुद्दे ने प्राप्त किया है (आपका उपयुक्त मामले में “आवेदन किया है)।”

#### खण्ड 3.02 बोली बाण्ड और गारन्टियाँ

बोली बाण्ड या बोली की गारन्टियाँ साधारण आवश्यकताएँ हैं लेकिन इतनी इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बालीकार हतोन्माह हो जाए। बोली खोलने के पश्चात् जैसे ही सम्भव हो बोली बाण्ड अथवा गारन्टियाँ अमफल बोलीकारों को गिरा कर देनी चाहिए।

#### खण्ड 3.03 सविदा की शर्तें

सविदा के प्रशामन और उसके अधीन किए गए किसी परिवर्तनों से दो संविदा की शर्तों में ऋणी और ठेकेदार या सम्भरण के अधिकार



और दायित्व और यदि ऋणी द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया है तो उनके अधिकांश और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तों, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्देशन बिन्दुओं से किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

#### खण्ड 3.04 विशिष्टीकरणों की स्पष्टता

जहाँ तक सम्भव हो पूर्ण किए जाने वाले कार्य, सम्भरित किए जाने वाले माल और सेवाओं और सुपुर्दगी या संस्थापन के स्थान को विशिष्टीकरणों में स्पष्ट और यथार्थ रूप से घोषित करना चाहिए। आलेख विशिष्टीकरणों के मूल विषय के अनुरार होने चाहिए, जहाँ पर ऐसा नहीं होगा वहाँ पर मूल विषय ही प्रधान रहेगा। विशिष्टीकरण में उन मुख्य शर्तों या आधारों की पहचान होनी चाहिए, जिनकी बोलियों का मूल्यांकन करने समय और उनकी तुलना करने समय ध्यान में रखा जाएगा इसके अतिरिक्त कोई अन्य सूचना, स्पष्टीकरण, विशिष्टीकरणों में हुई गलतियों को ठीक करना अथवा उनमें परिवर्तन करने के सम्बन्ध में उन सभी की तुरन्त सूचना भेजी जाएगी जिन्होंने मूल बोली दस्तावेजों के लिए आवेदन किया है। बोली के आमंत्रण में पात्र स्रोत देश निविष्ट होने चाहिए और अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयातों के लिए यदि कोई प्रावधान हो तो वह भी निविष्ट होना चाहिए। जिन मामलों में निधि औपचारिक खरीद अन्तर्राष्ट्रीय निविदा (देखिये खण्ड 1.02) में निधि क्रियाविधियों के लिए सहमत हो गई है उनको छोड़कर विशिष्टीकरण का हममें इस प्रकार उल्लेख होना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली लगाने वालों की अनुमति और प्रोत्साहन मिले।

#### खण्ड 3.05 मानवण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या मान है तो विशिष्टीकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्य वस्तुएँ जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

#### खण्ड 3.06 बाण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विगेषनाओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टीकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल बाण्ड नाम, सूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाण्ड वाले मामले में विशिष्टीकरण को उन चिह्नों पण्यवस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिनती-जुलती है और कम से कम उन विशिष्टीकृत के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं।

#### खण्ड 3.07 संविदाओं को अस्तर्गत खर्च

चूंकि निधि के ऋण का उपयोग पात्र स्रोत देशों के क्षेत्र में उत्पादित माल के लिए अपात्र स्रोत देशों से अनुमति आयात के लिए और पात्र स्रोत देशों से भेजी गई सेवाओं के लिए किए जाने वाले व्यय में वित्तदान करने तक ही सीमित है इसलिए संविदा के अन्तर्गत बोली दस्तावेजों में ठेकेदार अथवा सम्भरक को अपने व्यय तदनुसार सीमित रखने चाहिए, या अपने दिवरण-पत्रों या बीजकों में अपात्र स्रोत देशों में किए गए खर्चों का बोध कराना चाहिए। जिन माल और सेवाओं के लिए निधि वित्तदान करती है उनके भौगोलिक मूल उद्गम और उनके प्रमुख संघटकों से सम्बन्धित सूचना की आवश्यकता निधि की ग्रांथिकीय उद्देश्यों के लिए होती है ठेकेदार अथवा सम्भरकों को बोली दस्तावेजों में आवश्यक सूचना भेजनी चाहिए।

#### खण्ड 3.08 बोलियों की कीमत लगाना

चूंकि निधि ऋण जापान येन में वर्गीकृत किया गया है, बोली का मूल्य जापान येन में दर्शाया जाना चाहिए लेकिन बोली मूल्य का वह भाग जिसको बोली लगाने वाला ऋणी के देश में खर्च करना चाहता है उसका वर्णन ऋणी को मुद्रा में किया जाना चाहिए।

#### खण्ड 3.09 संविदा की कीमत

संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में खर्च करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

#### खण्ड 3.10 मूल्य समंजन कण्डिकाएं

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है। यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता तो उपयुक्त मामलों में संविदा की कीमतों में समंजन (उतार-चढ़ाव) के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए ताकि वही प्रावधान सभी बोलियों में लागू किया जा सके माल की सप्लाय के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्तर सुपुर्द किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए। ये मार्ग-निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उपायों के परिचय का आभाम नहीं कराती हैं जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

#### खण्ड 3.11 अग्रिम भुगतान

खर्च चलाने के लिए संविदा के सप्पावन पर अग्रिम रूप से किए गए कुल भुगतान का प्रतिशत उचित होना चाहिए। अन्य दिए जाने वाले अग्रिम धन जिसे काम में आने वाले माल की साईट पर सुपुर्दगी के लिए भी बोली दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए।

#### खण्ड 3.12 गारन्टी, निष्पादन बाण्ड और रोक रक्खी गई धनराशि

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारन्टी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा। यह जमानत या तो बैंक गारन्टी द्वारा अथवा निष्पादन बाण्ड द्वारा दी जा सकती है इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने के बाद भी हममें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारन्टी या अमेकित बाण्ड की धनराशि को बोली दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की सप्लाय के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह बांछनीय होगा कि बैंक गारन्टी अथवा बाण्ड की अपेक्षा गारन्टी निष्पादन के लिए रोक रक्खी गई धनराशि का ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोक रक्खी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारन्टी अथवा बाण्ड चुना जाता है तो यह केवल नाममात्र धनराशि के लिए होना चाहिए।

#### खण्ड 3.13 बीमा

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्मों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

7845/88-2

**खण्ड 3 14 चुकाई जाने वाली क्षति और बोनस प्रावधान**

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होना है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से सम्बद्ध प्रावधान शामिल होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा सविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जबकि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए।

**खण्ड 3 15 बाध्यकारी परिस्थिति**

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई सविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबन्धित करते हुए इस सम्बन्ध में वाक्यांश होने चाहिए कि सविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को पूरा न करना उस हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों (फोर्न मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है (सविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है।)

**खण्ड 3 16 भाषा की व्याख्या**

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन-सी भाषा प्रमुख है।

**खण्ड 3 17 मण्डलों का निपटान**

मण्डलों के निपटान से सम्बन्धित व्यवस्थाएँ सविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएँ अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर आधारित होने चाहिए।

**अनुच्छेद IV****बोली खोलना, मूल्यांकन और ठेका देना****खण्ड 4 01 बोलियों के आमंत्रण और प्रस्तुत करने के बीच का समय**

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकांश सविदा की महत्वता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारण अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिन की स्वीकृति दी जानी चाहिए। जहाँ पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहाँ पर प्रत्याशित बोलीकारों का अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली भाँति देखभाल करने के लिए आमंत्रण पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए। किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

**खण्ड 4 02 बोली खोलने की क्रियाविधि**

बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली खोलने के लिए तिथि, समय और स्थान की बोली आमंत्रण में धारित किया जाना चाहिए और सभी बोलियाँ निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों का बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल वनराशि जोर में पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

**खण्ड 4 04 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन**

बोली खलने के पश्चात् किसी भी बोली बालने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर

कोई प्रभाव न पड़े। ऋणी किसी भी बोली बालने वाले से अपने बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलीकार को अपनी बोली के वास्तविक एवं मध्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

**खण्ड 4 04 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि**

कानून द्वारा यथा अनेधन को छोड़कर बोली के खलने के बाद बोली से सम्बन्धित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से सम्बन्धित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति का जो इन क्रियाविधियों से औपचारिक रूप से सम्बन्धित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सकल बोलीकार के लिए सविदा के निर्णय को धारित नहीं कर दिया जाता है।

**खण्ड 4 05 बोलियों की जाँच**

बोलियों के खलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय सम्बन्धी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार है, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलियाँ सामान्य अन्वया रूप से सही हैं? यदि बोलियाँ मूल रूप में विशिष्टीकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्वया मूल रूप में बोली सम्बन्धी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए और बोलियों के मिलान के लिए नकली की विश्लेषण किया जाना चाहिए।

**खण्ड 4 06 बोलीकारों की पूर्व प्रस्ताव**

पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सबूत सविदा को सम्बन्धी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का काम कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार इन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

**खण्ड 4 07 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान**

बोलियाँ का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिए। अन्तिम गलतियों के लिए समझित बोली की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्यकुशलता एवं क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीका की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो वे बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टीकृत मानदंड के अनुसार स्पष्ट पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समझन कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएँ जिनमें मूल्य आका जाता है बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होना चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनिमय की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर हानी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियाँ खलने के दिन तक उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू हानी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय अधिसूचित करने समय विनिमय की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

बोली की मूल्यांकन और मिलान की रिपोर्ट जिसमें वे विशेष कारण निर्धारित किए गए हैं जिन पर न्यूनतम मूल्यांकन बोली का निर्धारण आधारित है ऋणी या उसके सलाहकारों द्वारा तैयार की जानी चाहिए।

**खंड 4.08 बोलियों को अस्वीकृत करना :**

बोली वस्तावजों में सामान्यतया यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ पूर्ण उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियां आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए भी तब औचित्य देने चाहिए जहां (क) बोलियां, बोली वस्तावज के आगव के अनुसार नहीं है या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति सिद्ध की गई है और या तो विशिष्ट-कारण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिए मूल आमंत्रण में भांगी गई पण्यवस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करे। विवेक स्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकार के साथ सौदा कर सकता है।

**खंड 4.09 संविदा का निर्णय :**

संविदा का निर्णय उम बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्य-वस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिए जिम्मेवारी ले।

बोलियों का विश्लेषण करने के पश्चात् बोलियों के विश्लेषण की प्रतियां और निर्णय के लिए प्रस्ताव ऐसे प्रस्तावों के लिए कारणों सहित निधि के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

**अनुच्छेद V****सलाहकारों के उपयोग के लिए मर्ग-दर्शन****खंड 5.01 सलाहकारों की स्वतंत्रता :**

निधि के अन्तर्गत परियोजना के वित्तबान के संबंध में नियुक्त की गई सलाहकार पाटियां हम दृष्टिकोण से स्वतंत्र होंगी कि उनकी सलाह और आलोच, विशिष्टिकरण और उनके द्वारा बनाए गए निविदा वस्तावज राष्ट्रीय, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक पक्षपात से मुक्त हैं।

सलाहकार इंजीनियर जो कि ठेकेदारों अथवा विनिर्माण पाटियों से मिले हुए हैं केवल तभी उपयोग में लाए जा सकेंगे जबकि स्वयं और उनके साथी एक ही परियोजना पर किसी भी अन्य क्षमता से कार्य के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। सलाहकार इंजीनियरों के मामले में जो कि विनिर्माताओं के साथ लगे हुए हैं और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने हैं केवल यह सुनिश्चय करने के लिए ही ध्यान नहीं रखा जाएगा कि वह कम्पनी जिससे सलाहकार संबंधित है परियोजना के किसी भी भाग पर भविष्य में बोली खोलने के लिए न केवल अयोग्य घोषित कर दी जाएगी बल्कि वे विशिष्टिकरण में निष्पक्ष होंगे और उनका प्रतियोगिता के आधार पर पालन किया जाएगा।

**खंड 5.02 सलाहकारों का चयन :**

सलाहकार पाटियों के चयन के लिए औपचारिक प्रतियोगात्मक बोली क्रियाविधियों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, चयन के दौरान ऋणी, प्रत्याशित पाटियों की उचित संख्या पर विचार करेगा जिसमें निधि द्वारा अधिसूचित पाटियां भी शामिल होंगी, जिनसे पात्र श्रोत देशों द्वारा उचित तथा स्वतंत्र सेवाएं प्रदान करने की संभावना हो सकती है।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण कम से कम तीन पाटियों तक बढ़ाया जा सकेगा। प्राप्त होने पर प्रस्तावों की पहले गुणात्मक आधार पर तुलना की जानी चाहिए अर्थात् योजना बनाने के संबंध में, अनुसूचियों, नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का अनुभव और क्षमताएं, दिए गए कार्य के लिए सबसे योग्य समझी गई पार्टी अथवा पाटियों के चयन के पश्चात् पूर्ण निर्णय पर पहुंचने के लिए संविदा के मूल्य और अन्य वित्तीय शर्तों पर मानने के लिए धान्यीत प्रारम्भ की जानी चाहिए। निधि द्वारा परियोजना की तैयारी और पर्यवेक्षण के लिए की गई सहायता के लिए ऋणी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अथवा पहले ही नियुक्त किए गए सलाहकारों के चयन के अनुमोदन का अधिकार निधि को प्राप्त है।

**अनुबन्ध 3****प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र**

संख्या

दिनांक :

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय,

आर्थिक कार्य विभाग,

यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मजल

पासियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय:—1979-80 के लिए येन क्रेडिट सं० आई०बीपी 5/पार-  
योजना सहायता के अन्तर्गत जापान से.....का  
आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित यून क्रेडिट आई बीपी 5 (परियोजना सहायता) के अधीन ..... से .....  
..... जो कि ..... के आयात के संबंध में .....  
..... (बैंक का नाम) जो कि वही होना चाहिए जो नीचे (ड) में  
सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साक्ष्यपत्र खोलने के लिए दिया गया है  
को प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे  
प्रस्तुत करते हैं:—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता।

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके:—क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश।

(च) यदि कोई हो तो पात्र से इतर श्रोत देशों से आयातित संबद्धों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल अंश पर निःशुल्क मूल्य (येन में)।

(ज) यदि कोई हो, तो भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन में)।

(झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक।

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता :—

- (1) राष्ट्रिकता।
- (2) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शायरों का प्रतिशत।
- (3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या सम्भरक निवास स्थान।
- (4) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।

(ढ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय दिये जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)।

(ण) पोतलदान अनुदेश वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिये।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत ओ ई सी एफ को इसे अधिसूचित किया गया है।

#### अनुबन्ध-4

##### प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

संख्या एक

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इण्डिया,  
टोकियो शाखा,  
टोकियो (जापान)

विषय :—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार संख्या आई० डी० पी०-5 के अधीन आयात साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को दिए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एवद्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री ..... के नाम में ..... येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक ओ० ई० सी० एफ० भारतीय दूतावास टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपके कण्ड से किया जाएगा। भुगतान के बाद ओ० ई० सी० एफ० को आवश्यक दस्तावेज भेजकर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ० ई० सी० एफ० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा सीधे ही व्याज दिया जाएगा। बैंकों के अन्य खर्च जिसमें साख-पत्र खोलने, रख-रखाव करने और साख-पत्रों को जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल हैं क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्च भी विदेशी संभरक को ही देना पड़ेगा और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ० ई० सी० एफ० से नहीं किया जा सकता।

यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने के लिए है। इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए आगे के नए साख-पत्र या साख-पत्र में वाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार पत्र ..... तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. आयातक ..... को उनके पत्र संख्या ..... दिनांक ..... के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक ..... उनसे निवेदन है/किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि वे बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्व ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा कर दी जाती है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी में जमा करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई० टी० सी० (पी० एन०)/68 दिनांक 30-8-68 संख्या 233 आई० टी० सी० (पी० एन०)/68 दिनांक 24-10-1968, संख्या 132-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 5-10-1971, सं० 74 आई० टी० सी० (पी० एन०)/74 दिनांक 31-5-74 और संख्या 103 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज 843 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिटर्स फार परचेजिस एटसेकट्रा फ्रोम एग्जोड-परचेजिस अन्डर क्रेडिट/लोन एग्ग्रीमेंट अन्डर डिटेलड हेड" "2.7 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई आई डी० पी 5 फार 1979-80 फ्रोम जापान क्रेडिटस फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान" है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनको चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रोषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,  
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

पहली मंजिल, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग,  
संसद मार्ग, नई दिल्ली ।

जिस मामले में तुल्य रूपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० विनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पत्र पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रूपया का पूरा व्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हों तो, बैंकिंग खर्चें म्याज और बैंक आफ इण्डिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खर्चें इण्डियन बैंक और बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2, समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेकुबमी मूडो बिल्डिंग 4-1, मोहटिमेंची 1-कोमे चियोडा-कू टोकियो 100, जापान।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी।

#### अनुबन्ध 5

(ओ० ई० सी० एफ०-एल०सी-1 प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय/साख-पत्र  
(माल के लिए लागू)

विनांक .....

सेवा में,

..... यह साख-पत्र (ऋणी) और विदेशी  
..... आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए  
[संभरक का नाम और पता] ऋण करार सं० .....  
दिनांक ..... के  
अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय सहोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए वर्षानी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० ..... खोल दिया है जो ..... येन (..... येन कह सकते हैं) की कुल धनराशि में अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है :-

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

क्लीन ग्रान बोर्ड, समुद्री पोतलवान बिल जिनमें लिए गए आवेश का पूरा सेट हों ब्लैक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "फ्रेट" एवं "नोटिफाइट"

अन्य दस्तावेज जिसमें ..... से ..... तक लदान का सत्यापन दिया गया हो (संविदा संख्या .....)  
(यदि कोई हो) के संदर्भ में माल का संक्षिप्त विवरण प्रांशिक पोतलवान स्वीकृत है। वाहनान्तरण यदि स्वीकृत है।

पोतलवान बिल जो ..... से बाव की तिथि का नहीं होना चाहिए।

आदेशों को डाफ्ट ..... 19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी डाफ्ट और दस्तावेजों पर यह प्रकन होना चाहिए।

"अपरिवर्तनीय साखपत्र संख्या ..... दिनांक ..... 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ संख्या (संख्याएं) (यदि कोई हो)" यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एतद्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी डाफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशों की दस्तावेजों की सुपुर्वगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

अब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट "यूनि-फार्म कस्टम एण्ड प्रेक्टिस फार डाकुमेन्ट्स क्रेडिटस (1974 रिवीजन), इन्टरनेशनल बैंम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन नं० 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश :

उपयुक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि को सौदा करेंगे।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हमें डाफ्ट्स और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य भेजें कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा ..... को भेज दिए गए हैं।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्चें संभरक के लेख के लिए हैं।

भवदीय,

(.....)

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें

यह भुगतान हमारी साख-पत्र सं० ..... का अभिन्न अंग है

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि ..... येन जो कि कुल संविदा मूल्य के ..... प्रतिशत है

आपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हों)

धनराशि ..... येन जो कि कुल संविदा मूल्य का ..... प्रतिशत है

आपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख

3. पोतलवान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि ..... येन  
संविदा जो कुल मूल्य का ..... प्रतिशत है

टिप्पणी :- पोतलवान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद 6

(प्रपत्र-प्रोईसीएन-एलसी-2)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(सेवाओं के लिए लागू)

सेवा में,

दिनांक

..... यह साख-पत्र ऋणी और विदेशी  
 ..... आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए  
 ..... ऋण करार संख्या .....  
 ..... विनांक ..... के  
 ..... अनुमरण में जारी किया गया है।

[संभरक का नाम व पता]

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करने हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण  
 स्मॉरी मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एंड साइट द्वारा उपलब्ध रकम या  
 रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० .....  
 ..... खोल दिया है जो येन .....  
 ..... (येन ..... पहले) की  
 कुल धनराशि से अधिक नहीं है।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा .....  
 ..... और परियोजना .....)  
 से संबंधित दस्तावेजों को नवी कराना है। सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट  
 ..... से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज "अपरिवर्तनीय साख-पत्र संख्या .....  
 ..... विनांक ..... के अन्तर्गत भुना लिए  
 गए हैं" से चिन्हित होने चाहिए।

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एनडब्ल्यू वचन देने हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों  
 का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट, प्रस्तुत करने पर और आवे-  
 शितों को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट  
 "यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रेक्टिस फार डॉक्यूमेंटरी क्रेडिटम (1974 रिवीजन),  
 इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स नं० 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश :

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी अथवा इसके मनोनीत प्राधि-  
 कारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के  
 पश्चात् इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित  
 भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए। प्रारम्भिक भुगतान के  
 मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाय लाभकारी विवरण को  
 आवश्यकता है।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचन-  
 बद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने  
 भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों का धनराशि  
 का मोल तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार  
 प्रेषित करने का वचन देने हैं।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और  
 मयौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भजे जाएंगे।

4. इस साख के अन्तर्गत बैंक को सभी खर्चें सभरको के लेखों के  
 लिए हैं।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साख-पत्र सं० ..... का  
 एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि ..... येन

कुल संविदा मूल्य का ..... प्रतिशत है

आपेक्षित दस्तावेज :— लाभकारी विवरण की अन्तिम भुगतान तिथि :—

2. भुगतान वृद्धि

सम्पूर्ण योग की धनराशि ..... येन

कुल संविदा मूल्य का ..... प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :—

देय धनराशि ..... अन्तिम भुगतान तिथि

येन .....

पहली किश्त येन .....

दूसरी किश्त येन .....

अपेक्षित दस्तावेज : (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी  
 किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका  
 एक प्रपत्र यहाँ संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक .....

संदर्भ सं० .....

सेवा में,

[संभरक का नाम और पता]

मन्वर्तः— ऋण करार सं० ..... के अन्तर्गत  
 ..... परियोजना से संबंधित ..... के  
 नाम में ..... येन के लिए .....  
 ..... द्वारा जारी किए गए साख-पत्र की सं० .....  
 विनांक .....

में, प्रयोद्देश्यकारी, प्रतिनिधि (शुष्की) एतद्द्वारा .....  
 और ..... के बीच हुए समझौता स. ....  
 ..... दिनांक ..... में निहित शुभ-  
 तान की शर्तों के अनुसार समुदाय आर्थिक सहायता निधि द्वारा ...  
 ..... की धनराशि (..... येन केवल) प्राप्त करने  
 के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करना है।

(शुष्की)

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

**विशेष अनुदेशः—**

साप्ताहिक निष्पादन का विवरण इसमें सलग्न पत्र में वर्णित जाएगा।

**MINISTRY OF COMMERCE**

PUBLIC NOTICE NO. 37—ITC(PN)/80

New Delhi, the 1st October, 1980

**IMPORT TRADE CONTROL**

Subject : Licensing conditions in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of Y 2.7 Billion extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF).

The terms and conditions governing the issuance of import licences in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of Y 2.7 Billion for Telecommunication Project (II) extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

[Issued from F. No. IPC/23/3/80]

**Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 37—ITC(PN)/80**

New Delhi, the 1st October, 1980

*Licensing Conditions in Respect of Imports of Goods and Services under the Yen Credit of Y 2.7 Billion for Telecommunication Project (II) Extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF)*

**Section I—General Conditions :**

I(i) The Yen Credit of Y 2.7 billion extended by the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Telecommunication Project of the DGP&T is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Y 3,000 million, (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&F, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will made debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-p. 5". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&F forwarding the import licence to D.G.P&T, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii) Import Licence(s) can be issued only in favour of DGP&T on CIF basis.

I(iv) Depending on the convenience of DGP&T more than one import licence may be issued under this credit but the total value must not exceed Y 3,000 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by DGP&T, be granted upto 31-12-84. Request for further extension, if any should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agents commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are NOT acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facilities of letter of authority for the establishment of letter of credit acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I(x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on each basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

"..... Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of.....".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-84.

**Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.**

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order

and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be born in mind :—

- Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.
- Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.
- Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

- Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.
- Where the number of qualified suppliers is limited.
- Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.
- Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

- Formal Selective International Tendering.
- Informal International Competitive Procurement.
- Direct Purchases from a single supplier.

DGP&T should prepare a detailed report on the evaluation and comparison of bids setting forth the specific reasons/justifications on which the lowest evaluated bid is based and submit it in triplicate along with bid analysis statements/sheets supported by documentary evidences, if any to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section), North Block, New Delhi who will obtain the necessary approval of the same from the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF). It should be noted that purchase contracts will be notified by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Japan Section) to the O.E.C.F. only after obtaining the OECF approval of the report etc.

II(iv) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 5 for 1979-80 the details of which are given in Section VI below.

II(v) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

#### II(vi) Eligibility of Supplier

The Suppliers shall be nationals of the eligible source countries, or juridical persons governed substantially by national of the eligible source countries, satisfying the following conditions :

- a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries.

(b) that a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source country; and

(c) such juridical persons have been registered in the eligible source countries.

#### II(vii) Declaration in Contract

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in \_\_\_\_\_ (eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that \_\_\_\_\_ (Name of company) has been incorporated and registered in \_\_\_\_\_ (name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

#### II(viii) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formulae :

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

### Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

- The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 8th May, 1980 concerning the Yen Credit No. ID-P5 (Project Aid) for Tele-communication Project (II) and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.
- Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P.5 dated 8th May, 1980 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).
- The Overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.
- Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vii)

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.



**Section IV—Contract Approval by OECF**

IV(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both DGP&T and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects together with two photo of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

(ii) The above procedure will also apply to all contract—amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

(iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. JP-P.5 (Project Aid) for Telecommunication Project (ii).

**Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure**

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance Department of Economic Affairs, Japan Section, DGP&T and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the DGP&T should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisations in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would *inso facto* apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of the goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) All charges on account of opening, maintenance and on the operation of the letter of credit will be to the account of Overseas Suppliers. Bank of India, Tokyo will, therefore, recover all these charges from the Suppliers' Bank, charges for handling and negotiating the documents and other incidentals will also be borne by the suppliers.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B. cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF the B.O.I. will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (M/o Finance) on 25-3-1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest payment by the Embassy of India in Japan will be recovered from the P&T Department (vide Section VI(iv) infra).

**Section VI—Responsibility for rupee deposit**

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of DGP&T as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the DGP&T make the rupee deposits at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis

Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843-Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/Loan Agreements Loans from the Government of Japan-2.7 billion Yen Credit No. ID-P.5 for Telecommunication Project (II)." The provisions regarding calculation and deposit of interest charges mentioned in the above said Public notice of 31-5-1974 will, however, not be applicable, as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VI(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-68, No. 132 ITC (PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

**Note :** Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charges etc., made by Embassy of India, Tokyo, to the BOI, Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI(i) of Section VI above and deposited in favour of the Principal Accounts Officers, Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA&A will be issuing suitable advices.

**Section VIII—Miscellaneous provisions**

VIII(i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipment and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

**VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions**

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

**VIII(iii) Disputes**

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

**VIII(iv) Future Instructions**

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P.5 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

**VIII(v) Breach or violation**

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

**VIII(vi) List of Annexures**

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—Broad Guidelines for Procurement.

Annexure III—Request for issue of Letter of Authority.

Annexure IV—Form of Letter of Authority.

Annexure V—Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).

Annexure—VI Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

**ANNEXURE I****List of Eligible Source Countries****A. Developing Countries and Territories****(a) Non-OPEC Developing Countries :****I. AFRICA, North of Sahara :**

Egypt  
Morocco  
Tunisia

**II. AFRICA, South of Sahara :**

Angola  
Botswana  
Burundi  
Cameroon  
Capo Verde Islands  
Central African Rep.  
Chad  
Comoro Islands  
Congo, People's Republic of Dahomey  
Equatorial Guinea (1)  
Ethiopia  
Gambia  
Ghana  
Guinea  
Ivory Coast

Kenya  
Lesotho  
Liberia  
Malagasy Republic  
Malawi  
Mali  
Mauritania, Mauritius  
Mozambique  
Niger  
Portuguese Guinea  
Reunion  
Rhodesia  
Rwanda  
St. Helena and dep (2)  
Sao Tomo and Principe  
Senegal  
Seychelles  
Sierra Leone  
Somalia  
Sudan  
Swaziland  
Terro. Afars and Issas  
Togo  
Uganda  
Un. Rep. of Tanzania  
Upper Volta  
Zaire Republic  
Zambia

**III. AMERICA, North and Central**

Bahamas  
Barbados  
Belize  
Bermuda  
Costa Rica  
Cuba  
Dominican Republic  
El Salvador  
Guadeloupe  
Guatemala  
Haiti  
Honduras  
Jamaica  
Martinique  
Mexico  
Netherlands Antilles  
Nicaragua  
Panama  
St. Pierre & Miquelon  
Trinidad and Tobago  
West Indies (Br.) n.l.c.  
(a) Associated States (3)  
(b) Dependencies (4)

**IV. AMERICA, South**

Argentina  
Bolivia  
Brazil  
Chile  
Colombia  
Falkland Islands  
French Guiana  
Guyana  
Paraguay

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following Islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(4) Main islands : Montserrat, Cayman, Turks, and Caicos, and British Virgin Islands.

Peru  
Surinam  
Uruguay

Malta  
Spain  
Turkey  
Yugoslavia

## V. ASIA, Middle East :

Bahrain  
Israel  
Jordan  
Lebanon  
Oman  
Syrian Arab Republic  
United Arab Emirates (1)  
Yemen Arab Republic  
Yemen, People's D.R. (2)

## (a2) Member or Association Countries of OPEC :

Algeria  
Bolivia  
Libyan Arab Republic  
Gabon  
Nigeria  
Ecuador  
Venezuela  
Iran  
Iraq  
Kuwait  
Qatar  
Saudi Arabia  
Abu Dhabi  
Indonesia

## VI. ASIA, South

Afghanistan  
Bangladesh  
Bhutan  
Burma  
India  
Maldives  
Nepal  
Pakistan  
Sri Lanka

## ANNEXURE II

## Guidelines for Procurement under the Loan

## TABLE OF CONTENTS

[ Article Number	Title	Page No.
Article I. General		
Section 1.01	Introduction	
Section 1.02	Procedures Other than Formal Open International Tendering	
Section 1.03	Type and Size of Contracts	
Article II. Advertising and Prequalification		
Section 2.01	Advertising	
Section 2.02	Prequalification of Bidders	
Article III. Bidding Documents		
Section 3.01	References to the Fund	
Section 3.02	Bid Bonds or Guarantees	
Section 3.03	Conditions of Contract	
Section 3.04	Clarity of Specifications	
Section 3.05	Standards	
Section 3.06	Use of Brand Names	
Section 3.07	Expenditures under Contracts	
Section 3.08	Pricing of Bids	
Section 3.09	Contract Price	
Section 3.10	Price Adjustment Clauses	
Section 3.11	Advance Payments	
Section 3.12	Guarantees, Performance Bonds and Retention Money	
Section 3.13	Insurance	
Section 3.14	Liquidated Damage and Bonus Clauses	
Section 3.15	Force Majeure	
Section 3.16	Language Interpretation	
Section 3.17	Settlement of Disputes	
Article IV. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract		
Section 4.01	Time Interval between Invitation and Submission of Bids	

## VII. ASIA, Far East :

Brunei  
Hong Kong  
Khmer Republic  
Korea, Republic of  
Laos  
Macao  
Malaysia  
Philippines  
Singapore  
Taiwan  
Thailand  
Timor  
Viet-Nam, Rep. of  
Viet-Nam Dem. Rep.

## VIII. OCEANIA

Cook Islands  
Fiji  
Gilbert & Ellice Is.  
French Polynesia (3)  
Nauru  
New Caledonia  
New Hebrides (Br. and Fr.)  
Niue  
Pacific Islands (US) (4)  
Papua New Guinea  
Solomon Islands (Br.)  
Tonga  
Wallis and Futuna  
Western Samoa

## IX. EUROPE :

Cyprus  
Gibraltar  
Greece

- (1) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
- (2) Including Aden and various sultanates and emirates.
- (3) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, The Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
- (4) Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

Section 4.02 Bid Opening Procedures	.	.
Section 4.03 Clarification or Alteration of Bids	.	.
Section 4.04 Procedures to be Confidential	.	.
Section 4.05 Examination of Bids	.	.
Section 4.06 Postqualification of Bidders	.	.
Section 4.07 Evaluation and Comparison of Bids	.	.
Section 4.08 Rejection of Bids	.	.
Section 4.09 Award of Contract	.	.
Article V Guidelines for Use of Consultants	.	.
Section 5.01 Independence of Consultants	.	.
Section 5.02 Selection of Consultants	.	.
Attachment : Eligible Source Countries		

### Guidelines for procurement under the Loan

#### ARTICLE I

##### GENERAL

#### Section 1.01 Introduction

(a) These Guidelines set forth the rules which THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (hereinafter called "the Fund") generally applies to the procurement of goods and services for a development project which the Fund finances in whole or in part by its loan.

(b) The proceeds of the Fund's loan are required to be used with due attention to considerations of economy, efficiency and non-discrimination among countries which are eligible for procurement of the above-mentioned goods and services (such countries are hereinafter called "the eligible source countries"). The Fund considers that in most cases formal open international tendering is the best method for achieving the economical and efficient procurement of the goods and services required for the development projects it finances. The Fund therefore normally requires its borrowers to obtain goods and services through formal open international tendering.

(c) The application of these Guidelines to a particular project financed by the Fund, the extent to which bidding documents and procurement procedures are subject to review by the Fund to ensure conformity with these Guidelines, eligible source countries and provisions for permissible imports from non-eligible source countries shall be stipulated in the contractual documents for the loan extended by the Fund for that project.

(d) The ultimate responsibility for the procurement of goods and services on any projects rests with the owner of the project. Since the owner is usually also the borrower, the term borrower has been used in these Guidelines to refer to the owner as well. The rights and obligations of the borrower vis a vis bidders for goods and services to be furnished for the project are governed by the bidding documents issued by the borrower and not by these Guidelines, which are concerned only with the relationship between the borrower and the Fund.

#### Section 1.02, Procedures other than Formal Open International Tendering.

There may be special circumstances in which formal open international tendering may not be appropriate and the Fund may accept alternative procedures in cases of following :

- Where the borrower has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.
- Where the number of qualified suppliers is limited, e.g. of spare parts for existing equipment.
- Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested, or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.
- Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedures inapplicable for example in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement formulas may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

- Formal Selective International Tendering
- Informal International Competitive Procurement
- Direct Purchases from a Single Supplier

#### Section 1.03. Type and Size of Contracts

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items applied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable to the Fund except in exceptional circumstances.

In order to foster widespread competition, individual contracts for which bids are invited shall, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis. On the other hand, if it is technically and administratively possible to divide a project into contracts of a specialized character and such division is likely to be advantageous and to allow broader formal open international tendering the project shall be so divided.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantage for the borrower country.

#### ARTICLE II

##### ADVERTISING AND PREQUALIFICATION

#### Section 2.01. Advertising

On all contracts subject to formal open international tendering invitations to bid should be advertised in at least one newspaper of general circulation in the borrower's country. Copies of the invitation to bid for the advertisement should also be transmitted promptly to local representatives of the eligible source countries.

#### Section 2.02. Prequalification of Bidders

In case the Fund recognises necessity of prequalification of bidders, the Fund requires the use of prequalification. It should be done taking into account (i) the experience and past performance of each firm on similar work, (ii) its capabilities with respect to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial positions. Abbreviated specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for qualification. When prequalification is employed, all firms which are found to be qualified shall be permitted to bid.

#### ARTICLE III

##### BIDDING DOCUMENTS

#### Section 3.01. References to the Fund

Bidding documents should refer to the following language :

".....(name of borrower) ..... has received (or in appropriate cases 'has applied for') a loan from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in.....towards the cost of (name of project)."

#### Section 3.02. Bid Bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees are usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid Bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

*Section 3.03. Conditions of Contract*

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the borrower and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the borrower, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

*Section 3.04. Clarity of Specifications*

Specifications should set forth clearly and precisely as possible the work to be accomplished, the goods and services to be supplied and the place of delivery or installation. The drawings should be consistent with the text of the specifications; where they are not, the text shall govern. The specifications should identify the main factors or bases which will be taken into account in devaluating and comparing bids. Any additional information, clarification, correction of errors or alterations of specifications shall be sent promptly to all those who had requested the original bidding documents. Invitations to bid should contain an indication of the eligible source countries and any provision for permissible imports from non-eligible source countries.

Except where the Fund has agreed to procedures other than formal open international tendering (see Section 1.02) the specifications should be so worded as to permit and encourage the widest possible international bidding.

*Section 3.05. Standards*

If national standards to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that goods meeting Japan Industrial Standard or other international accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

*Section 3.06. Use of Brand Names*

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of a specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative goods which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

*Section 3.07. Expenditures under Contracts*

As the use of the Fund's loan is limited to financing expenditures for goods produced in the territories of the eligible source countries, permissible imports from non-eligible source countries and services supplied from the eligible source countries, the bidding documents should require the contractor or supplier to limit his expenditures under the contract accordingly or to identify expenditures in non-eligible source countries in his statements or invoices.

For statistical purposes the Fund requires information concerning their geographical origin of the goods and services it finances and of their major components. The bidding documents should require the contractor or supplier to furnish the necessary information.

*Section 3.08. Pricing of Bids*

As the Fund's loan is denominated in Japanese Yen, the bid price should be stated in Japanese Yen provided, however, that for the portion of the bid price which the bidder expects to spend in the borrower's country such portion should be stated in the borrower's currency.

*Section 3.09. Contract Price*

The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

*Section 3.10. Price Adjustment Clauses*

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

In appropriate cases, provision should be made for adjustment (upwards or downwards in the contract prices in the event changes occur in prices of the major cost constituents of the contract such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents so that the same provisions will apply to all bids.

A ceiling of prices adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

*Section 3.11. Advance Payments*

The percentage of the total payment to be made in advance from effectuation of the contract for mobilization expenses should be reasonable. Other advances to be made, as for example for materials delivered to the site for incorporation in the works, should also be clearly described in the bidding documents.

*Section 3.12. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money*

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

*Section 3.13. Insurance*

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

*Section 3.14. Liquidated Damage and Bonus Clauses*

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

*Section 3.15. Force Majeure*

The conditions of contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate stipulating that failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of contract).

*Section 3.16. Language Interpretation*

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, Eng-

lish should be added to the such documents and it is required to specify which is governing.

#### *Section 3.17. Settlement of Disputes*

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of contract. It is appropriate that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which has been prepared by International Chamber of Commerce.

### ARTICLE IV

#### **Bid Opening, Evaluation and Award of Contract**

##### *Section 4.01. Time Interval between Invitation and Submission of Bids*

The time allowed or preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 45 days should be allowed for international bidding. Where large civil works are involved, generally not less than 90 days should be allowed to enable prospective bidders to conduct investigations at the site before submitting their bids. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each project.

##### *Section 4.02. Bid Opening procedures*

The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted should be read aloud and recorded.

##### *Section 4.03. Clarifications or Alteration of Bids*

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask bidder to change the substance or price of his bid.

##### *Section 4.04. Procedures to be Confidential*

Except as may be required by law, no information relating to the examination clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

##### *Section 4.05. Examination of bids*

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

##### *Section 4.06. Postqualification of Bidders*

In the absence of prequalification, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

##### *Section 4.07. Evaluation and comparison of Bids*

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should

be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of the currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

A detailed report on the evaluation and comparison of bids setting forth the specific reasons on which the determination of the lowest evaluated bid is based should be prepared by the borrower or by its consultants.

##### *Section 4.08. Rejection of Bids*

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the cost estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revisions of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

##### *Section 4.09. Award of Contract*

The award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities or work not stipulated in the specifications or to modify his bid.

After bids have been analyzed, copies of the analysis of bids and proposals for awards, together with the reasons for such proposals, shall be submitted to the Fund for approval.

### ARTICLE V

#### **Guidelines for the Use of Consultants**

##### *Section 5.01. Independence of Consultants*

Consultant firms employed in relation to a project financed under the Funds shall be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and tender documents prepared by them shall be free of national, commercial or industrial bias.

Consulting engineers who are associated with contracting or manufacturing firms shall be used only if they disqualify themselves and their associates for work in any other capacity on the same project. In the case of consulting engineers who are affiliates of manufacturers offering consulting services steps shall be taken not only to ensure that the company to which the consultant is affiliated will be disqualified from future bidding on any part of the project, but also that specifications will be impartial and can be complied with on a competitive basis.

##### *Section 5.02. Selection of Consultants*

Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consulting firms. However, in the process of selection the borrower shall consider a reasonable

number of prospective firms, including those notified by the Fund, which can be expected to render competent and independent services from the eligible source countries. Invitations to submit proposals shall be extended to at least three firms. Proposals, when received, it should first be qualitatively compared, i.e., with respect to plans of approach, schedules, experience and capabilities of personnel to be assigned; after selection of a firm or firms considered to be best qualified for the assignment has been made, negotiations to agree upon the price and other financial terms of the contract should be opened so as to reach the final decision. The Fund reserves the right to approve the choice of the consultant to be employed or already employed by the borrower for the preparation and supervision of the project financed by the Fund.

## ANNEXURE III

## Request for issue of the letter of authority

No.

Date :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
U.C.O., Bank Building, 1st Floor,  
Parliament Street,  
New Delhi-110001.

Sub :—*Import of* *from Japan under the*  
*Yen Credit No. ID-P5 (Project Aid) for 1979-80.*

Sir,

In connection with the import of ..... from ..... under the above mentioned Yen Credit No. ID-P5 (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the ..... (name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned).

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in Yen).
- (h) Amount of Indian agents commission in (Yen), if any.
- (i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with Overseas suppliers.
- (k) Name and Address of the Overseas Supplier :
  - (i) Nationality.
  - (ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.
  - (iii) Nationality of the representatives and/or President of the Supplier.
  - (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

- (1) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the importer's bank in India.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

## ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,  
Tokyo Branch  
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. ID-P5—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen \_\_\_\_\_ favouring M/s. \_\_\_\_\_ as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interest as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto \_\_\_\_\_.

Yours faithfully,  
Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer— with reference to their letter No.—dated—.

2. Importers' Banker—. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-6-68, 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements—Loans from the Government of Japan—2.7 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.5 for 1979-80".

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India, Tokyo/Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Gbdo Building 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE V

Form OECF-LCT

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

To—

Date :

(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. ————.

dated—

between (Borrower) and the Overseas Economic Co-operation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. ———— in your favour for account of ———— for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of ———— (Say Yen ————) available by your draft at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in

Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight" and "Notify" Other documents

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. ———— (if any)

from ———— to ———— . Partial shipments are permitted. Transshipment is

permitted. Bills of lading must be

dated not later than ———— Drafts must be presented for negotiation not later than ————.

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under ———— irrevocable credit No. ————

, dated ———— and Import Reference

No. (s), ———— (if any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Bochure No. 290".

**Special Instructions to the negotiating bank :**

1. After obtaining the reimbursement for our payments from the Overseas Economic Cooperation Fund in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been air-mailed direct to ————.

3. All banking charges under this credit are for the account of suppliers.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By ————

(Authorised Signature)

**PAYMENT TERMS**

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. ————.

**I. Initial Payment :**

Amount : ————

being ———— % of the total contract price.



Required documents :

Latest presentation date :

**II. Intermediate Payment (if any)**

Amount : .....  
being .....% of the total  
contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

**III. Payment against Shipping Documents**

Amount : .....  
being .....% of the total  
contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment<sup>t</sup> against shipping documents.

**ANNEXURE VI**

**Form OECF-LC II**

**Irrevocable Letter of Credit**

(Applicable for Services)

Date :

To

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Name and address  
of the Supplier)

This Letter of Credit has  
been issued pursuant to  
Loan Agreement No.—  
dated—, between  
(Borrower) and The  
Overseas Economic Co-  
operation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. \_\_\_\_\_ in your favour for account of \_\_\_\_\_ for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y \_\_\_\_\_ (Say Yen \_\_\_\_\_) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. \_\_\_\_\_ with regard to \_\_\_\_\_ Project). Drafts must be presented for negotiation not later than \_\_\_\_\_

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_". This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of document to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

**Special Instructions to the negotiating bank :**

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned State of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from The Overseas Economic Cooperation Fund in accordance  
784 GI/80—4

with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the suppliers.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By : \_\_\_\_\_

(Authorized Signature)

**PAYMENT SCHEDULE**

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. \_\_\_\_\_

**I. Initial Payment**

Amount : .....  
being .....% of the total  
contract price.

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date :

**II. Progress Payment**

Aggregate amount : .....  
being .....% of the total con-  
tract price to be  
paid as follows :

Amount due	Latest presentation date
------------	--------------------------

1st Instalment : .....

2nd Instalment : .....

Required document : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

**STATEMENT OF PERFORMANCE**

Date :

Ref. No.

To

\_\_\_\_\_

(Name and address of the Supplier)

Re : Letter of Credit No. \_\_\_\_\_ dated  
issued by \_\_\_\_\_  
for \_\_\_\_\_ in favour of  
\_\_\_\_\_ concerning \_\_\_\_\_ Project  
under Loan Agreement No. \_\_\_\_\_

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issued a Statement of Performance to entitle \_\_\_\_\_ to receive the sum of \_\_\_\_\_ (Yen \_\_\_\_\_ only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ between \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_

(Borrower)

By : \_\_\_\_\_  
(Authorized Signature)

**Special Instructions :**

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

सार्वजनिक सूचना सं० 38—आईटीसी (पीएन) 80

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1980

विषय :— अप्रैल 1980-मार्च 1981 के लिए आयात नीति।

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 9—आई टी सी (पी एन)/80 दिनांक 15 अप्रैल, 1980 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1980-मार्च 1981 की आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उक्त आयात नीति में नीचे निविष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्न-लिखित संशोधन किए गए समझे जाएंगे :—

क्रम	आयात नीति	संदर्भ	संशोधन
सं०	1980-81	की पृष्ठ संख्या	
1	2	3	4
1.	24	अध्याय 15— द्विविध उपबन्ध	<p>विद्यमान पैरा 3 के बाद निम्न-लिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा :—</p> <p>“(19) गैस सिलेन्डरों का आयात 3-क (1) गैस सिलेन्डरों के आयात के लिए आवेदन पत्रों पर मुख्य नियंत्रक आयात नियंत्रित द्वारा मूल्य को ध्यान में न रखते हुए विचार किया जाएगा आवेदन पत्र पूंजीगत माल के आयात के लिए निर्धारित प्रपत्र में भेजे जाने चाहिए।</p> <p>2) आवेदन पत्रों पर देसी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए पालता के आधार पर विचार किया जाएगा। मुख्य नियंत्रक आयात नियंत्रित, नई दिल्ली शासनिक मंत्रालय और संबंध तकनीकी प्राधिकारियों के परामर्श से उपयुक्त मार्गनिर्देशन बिन्दु बतायेंगे जिससे कि आयात की अनुमति उसी सीमा तक की जा सके जिस सीमा तक बेसी ओतों से मांग की पूर्ति न हो सकती हो।</p> <p>(3) एल पी जी सिलेन्डरों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>(4) चिकित्सा गैस सिलेन्डरों के आयात की अनुमति वास्तविक उपयोगिताओं की पूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए दी जाएगी।</p> <p>(5) हाई प्रेशर सिलेन्डरों के आयात की अनुमति भी वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना</p>

1	2	3	4
			सं० 33-आई टी सी (पी एन)/80 दिनांक 19/8/1980 में किए गए प्रावधानों के अनुसार वास्तविक उपयोगिताओं को अतिरिक्त सामान के रूप में भी जाएगी। संघटकों के रूप में वास्तविक उपयोगिताओं को उन के आयात की अनुमति सम्पूर्ण लाइसेंसों के लिए क्रियाविध के अधीन दी जा सकती है।
2. 47	परिशिष्ट 1, प्रविष्टि सं० 6 (15)		यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
3. 82	परिशिष्ट 5, प्रविष्टि सं० 140 क (4)—हार्ड स्ट्रेण्ड ग्लाम फाट-बर प्रेक्कि और रोलिंगम।		यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
4. 87	परिशिष्ट 5 प्रविष्टि सं० 389		यह प्रविष्टि निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित की जाएगी :— “पीतल और कंसे इलेक्ट्रोडस, छड़ें/तार।”
5. 87	परिशिष्ट 5, प्रविष्टि सं० 409		यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
6. 87	परिशिष्ट 5 प्रविष्टि सं० 486 (4)		विद्यमान विवरण निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :— “कॉलिंग कैपेसिटर्स (पावर लाईन उपकरण के संघटक (1))”
7. 89	परिशिष्ट 5 प्रविष्टि सं० 486 (5) (1)		विद्यमान विवरण निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :— “10000 एम एफ डी मुख्य तक अधिकतम 50 बी और 50 बी से अधिक और 450 बी तक के रेटिंग के 2000 एम एफ डी मुख्य के रेटिंग के इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर्स।”

[मिस्त्र सं० आईटीसी/3/9/80 से जारी]

मणि नारायण स्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात नियंत्रित

PUBLIC NOTICE NO. 38—ITC(PN)/80

New Delhi, the 1st October, 1980

Subject : Import Policy for April 1980—March 1981.

Attention is invited to Import Policy for April 1980—March 1981 published under the Department of Commerce Public Notice No. 9-ITC(PN)/80 dated the 15th April, 1980.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the said Import Policy at the appropriate places indicated below :

S. No.	Page No. of Import Policy, 1980-81	Reference	Amendments
1	2	3	4
1.	24	Chapter 15- Miscellaneous Provisions.	After the existing para 111, the following new para shall be added :— “(xix) Import of Gas Cylinders III-A. (1) Applications for import gas cylinders will be considered by Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, irrespective of the value involved. The applications should be made in the form prescribed for import of Capital Goods. (2) Applications will be considered, on merits, having regard to indigenous production. The CCI&E New Delhi will formulate suitable guidelines in consultation with the administrative Ministry and the technical authorities concerned so that import is allowed to the extent the demand can not be met from the indigenous sources. (3) Import of LPG cylinders will not be allowed. (4) Import of medical gas cylinders will be allowed to meet the full requirement of Actual Users. (5) Import of high pressure cylinders will also be allowed as spares to Actual

1	2	3	4
			Users in accordance with the provisions made in the Ministry of Commerce Public Notice No. 33-ITC (PN)/80 dated 19-8-1980. As components their import may be allowed to Actual Users under the procedure for supplementary licences.
2.	47	Appendix 1, Entry No. 6(15)	This Entry shall be deleted.
3.	82	Appendix 5, Entry No. 140A (iv)—High Strength glass fibre fabric and rovings	This entry shall be deleted.
4.	87	Appendix 5, Entry No. 389	This entry shall be amended to read as under : “Brass and bronze electrodes, rods/wires.”
5.	87	Appendix 5, Entry No. 409	This entry shall be deleted.
6.	89	Appendix 5, Entry No. 486(4)	The existing description shall be amended to read as under :— “Coupling capacitors (components of power-line equipment).”
7.	89	Appendix 5, Entry No. 486(5)(i)	The existing description shall be amended to read as under :— “Electrolytic capacitors of rating not exceeding 50V with value upto 10,000 mfd., and above 50 V and upto 450V with value 2,000 mfd.”

[Issued from file No. IPC/3/9/80]

MANI NARAYANSWAMI,  
Chief Controller of Imports & Exports

